नईदुनिया

तापमान

भोपाल	15.0°	36.0°
इंदौर	16.0°	36.0°
जबलपुर	18.0°	36.0°
ग्वालियर	19.0°	38.0°
सागर	20.0°	38.0°

वर्ष- 79
(भोपाल : वर्ष 41 अंक 102, पृष्ठ 12)
चैत्र, कृष्ण अष्टमी संवत् 2082
बुधवार, 11 मार्च 2026
राजधानी संस्करण
कीमत: 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... मुख्यमंत्री ने ममलेश्वर में जलाभिषेक एवं ...

खेल... तनवीर सांघा के लिए खिताबी मैच से हटे एडम...

व्यापार... दुनिया की खाद्य जरूरतें पूरी करने की दिशा...

देश-विदेश... समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट ...

पीएम मोदी आज केरल व तमिलनाडु दौरे पर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली : पीएम मोदी 11 मार्च को केरल और तमिलनाडु की यात्रा पर जाएंगे। पीएम दोपहर लगभग 1:30 बजे केरल के एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद, शाम लगभग 5:45 बजे, प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।

लामिछाने व बालेन को दी बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर दी जानकारी में बताया कि उन्होंने नेपाल के रास्वपा के अध्यक्ष रवि लामिछाने और पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह से गर्मजोशी भरी टेलीफोन बातचीत की। उन्होंने दोनों नेताओं को उनकी चुनावी जीत और नेपाल के चुनाव में रास्वपा की बड़ी सफलता पर बधाई दी।

कल्याणकारी योजनाओं के लिए 33 हजार 240 करोड़ स्वीकृति

▶▶ युवाओं के लिए इंटर्न कार्यक्रम और औषधालय खोलने का निर्णय

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की आगामी पांच वर्षों तक निरंतरता के लिए लगभग 33 हजार 240 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस कार्यक्रम' को भी मंजूरी दी गई, जिसके क्रियान्वयन के लिए तीन वर्षों में लगभग 190 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम के अंतर्गत नि:शक्तजन को वृत्तिकर से मिलने वाली छूट को 31 मार्च 2030 तक जारी रखने का निर्णय लिया। इसके अलावा 'एक जिला एक उत्पाद' परियोजना के अंतर्गत सात जिलों में पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों के संरक्षण, विकास और विपणन के लिए 37 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इन जिलों में सीधी की दरी और कालीन, दतिया का गुड़, अशोकनगर का चंदेरी हाथकरघा वस्त्र, भोपाल की जरी-जरदोजी और जूट उत्पाद, धार का बाग प्रिंट, सीहोर के लकड़ी के खिलौने तथा उज्जैन के बटिक प्रिंट को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंगरौली जिले के चितरंगी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के लिए कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सहित सात नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मियों के 51 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण और खनिज क्षेत्रों में अवसंरचना तथा पेयजल आपूर्ति के लिए 6090 करोड़ रुपये की योजना को भी स्वीकृति दी गई।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के सुचारु संचालन के लिए 7127 करोड़ रुपये तथा योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 2064 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। जनजातीय कार्य विभाग को 1645 करोड़, महिला एवं बाल विकास विभाग को 3773 करोड़ तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत निवेश संवर्धन और स्टार्ट-अप नीति के क्रियान्वयन के लिए 11 हजार 361 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

विकास को गति मिलेगी: डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विद्युत वितरण अधोसंरचना को मजबूत करने और वितरण कंपनियों को सहायता देने के लिए भी आवश्यक वित्तीय निर्णय लिए। इन निर्णयों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएँ सुदृढ़ होंगी।

खास-खबरें

एनसीईआरटी ने बिना शर्त माफी माँगी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने सामाजिक विज्ञान की कक्षा आठ की पुस्तक में शामिल न्यायपालिका से जुड़े अध्याय को लेकर बिना शर्त माफी मांगी है। विवाद के बाद संबंधित पुस्तक की बिक्री पर रोक लगा दी गई और पूरी किताब को वापस बुला लिया गया है। परिषद ने कहा कि यह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को इस मामले पर नाराजगी जताई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा था कि न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

पात्र मतदाताओं के नाम नहीं हटेंगे: ज्ञानेश कुमार

नईदुनिया ब्यूरो, कोलकाता: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का उद्देश्य सही वोटरों को मतदान का अधिकार देना और अयोग्य व्यक्तियों को सूची में शामिल न होने देना है। आयोग का मुख्य लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो। कुमार ने कहा कि राज्य के कानून-व्यवस्था अधिकारियों को बिना किसी दबाव के कानून का पालन करना होगा।

नौशेरा में घुसपैठ नाकाम एक आतंकी ढेर

नईदुनिया ब्यूरो, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के झंगर-नौशेरा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया। सेना के अनुसार 10 मार्च को दोपहर लगभग तीन बजे क्षेत्र में दो आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि का पता चला था। इसके बाद सैनिकों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। एक आतंकवादी मारा गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। सेना ने जमीन और हवाई निगरानी के माध्यम से तलाशी अभियान तेज कर दिया है। पिछले पांच दिनों में राजौरी क्षेत्र में दूसरी बार सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है।

अमेरिका-इज़राइल राजदूतों को निकालने वाले देशों को ही जहाज निकालने की अनुमति मिलेगी

ईरान का तेल निर्यात पर शिकंजा, होर्मुज स्ट्रेट बंद

तेहरान/तेल अवीव, एजेंसी: ईरान ने कहा है कि वह एक लीटर तेल भी निर्यात नहीं होने देगा। फारस की खाड़ी के प्रमुख समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को लेकर ईरान ने नई शर्त रखी है। ईरानी सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया कि केवल उन्हीं देशों के जहाजों को गुजरने दिया जाएगा, जिन्होंने पहले अपने देश से अमेरिका और इज़राइल के राजदूतों को बाहर निकाला हो। अमेरिका और इज़राइल के साथ जारी जंग का आज ग्यारहवां दिन है। सोमवार को ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया, वहीं अमेरिकी नौसेना ने फारस की खाड़ी में ईरानी जहाजों को निशाना बनाया। इसी दिन ईरान ने इज़राइल पर एक टन की वारहेड मिसाइलें दागीं और बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। अमेरिकी सेना ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स पर हमले का फुटेज जारी किया।

ईरान पर बड़ा हमला करेंगे: ट्रम्प

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान पर अब तक के सबसे बड़े और तीव्र हमले किए जाएंगे। इस अभियान में बड़ी संख्या में लड़ाकू जेट और बमवर्षक विमान शामिल होंगे। इधर, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा कि ईरान किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। जो लोग ईरान को मिटाने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह लोग स्वयं संकट में पड़ जाएं।

तेल के कई जहाज होर्मुज स्ट्रेट पर रोके

होर्मुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से हर साल विश्व की लगभग बीस प्रतिशत तेल की आपूर्ति होती है। अमेरिकी चैनल ने बताया कि ईरान इस मार्ग से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, खासकर उन जहाजों पर जो अमेरिका के सहयोगी देशों के हैं। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है।

193 बच्चों की मौत

ईरान सरकार की प्रवक्ता ने दावा किया है कि अमेरिका और इज़राइल के हमलों में अब तक 193 बच्चों की मौत हो चुकी है। सबसे कम उम्र की पीड़ित आठ महीने की बच्ची है। चार महीने का नवजात भी घायल हुआ। इन हमलों में स्वास्थ्य क्षेत्र को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिसमें 11 स्वास्थ्यकर्मी मारे गए और 52 स्वास्थ्य सेवा इकाइयां क्षतिग्रस्त हुईं।

एयरस्पेस 72 घंटे तक बंद

इराक ने देश के हवाई क्षेत्र को अगले 72 घंटे तक बंद कर दिया है। यह निर्णय क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इसी बीच ईरान में रहने वाले हजारों अफगान नागरिक सीमा पार कर अपने देश लौट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ईरान में करीब 30 लाख से 50 लाख अफगान नागरिक रहते हैं।

80 हजार से अधिक सीरियाई लौटे

साथ ही, लेबनान से 80 हजार से अधिक सीरियाई लोग सीमा पार कर अपने देश लौट चुके हैं। अधिकांश लोग बिना सामान लिए निकल पड़े और फिलहाल रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं। शरणार्थियों के लिए आपातकालीन आश्रय की अब तक कोई मांग दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था लगातार समीक्षा की जा रही है।

राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता हुए निर्विरोध निर्वाचित

▶▶ अब 11 सीटों के लिए बिहार, ओडिशा और हरियाणा में 16 मार्च को मतदान तय

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली : दस राज्यों की 37 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में सात राज्यों के 26 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं।

कई राज्यों में विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिसके कारण इन नेताओं को बिना मतदान के ही राज्यसभा के लिए चुन लिया गया। महाराष्ट्र की सात सीटों में शरद पवार, रामदास आठवले, विनोद तावड़े, रामराव वडुकुटे, माया इवनाते, ज्योति वाघमारे और पार्थ पवार निर्विरोध चुने गए। तमिलनाडु की छह सीटों पर तिरुची शिवा, जे कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन, एम क्रिस्टोफर तिलक, एल के सुदीश, एम थंबीदुरई और अंबुमणि रामदास निर्वाचित हुए। पश्चिम बंगाल की पांच सीटों पर राहुल सिन्हा, बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और कोएल मलिक निर्विरोध चुने गए। असम की तीन सीटों पर जोगेन मोहन, तेरोस गोवाला और प्रमोद बोरो निर्वाचित हुए। (शेष पेज 10 पर)

नो-फॉल्ट पॉलिसी लागू, अलग एक्सपर्ट पैनल की जरूरत नहीं

कोविड वैक्सीन से हुए नुकसान का मुआवजा दे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार वैक्सीन से होने वाले नुकसान का मुआवजा दे। इसके लिए नो-फॉल्ट कम्पनसेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें किसी की गलती साबित न होने पर भी मुआवजा मिलेगा। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए अलग एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत नहीं है। (शेष पेज 10 पर)

मौतों के दावे और स्टडी

करुण्या की जुलाई 2021 में कोवीशील्ड वैक्सीन लगने के बाद मृत्यु हुई। परिवार ने बताया कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट्स आए थे। वहीं, 8 साल की श्री ओमत्री को मई 2021 में कोवीशील्ड डोज के सात दिन बाद थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हुआ और उसकी मौत हो गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्टडी में बताया गया कि अचानक हुई मौतों का कोविड वैक्सीन से सीधा संबंध नहीं है। 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों में यह अध्ययन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत की वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है और गंभीर साइड इफेक्ट्स अत्यंत कम हैं। भारत में दो वैक्सीन विकसित हुईं—कोवैक्सिन, जिसे भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के सहयोग से बनाया, और कोवीशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटिश फार्मूला से तैयार किया।

स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

▶▶ विपक्ष ने पक्षपात और सांसदों की आवाज दबाने का आरोप लगाया

▶▶ प्रियंका गांधी का बयान-नेता प्रतिपक्ष की सच्चाई को सहन नहीं कर पा रही सत्ता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने उन्हें सदन में पक्षपात करने और सांसदों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। प्रस्ताव पर 50 से अधिक सांसदों ने समर्थन दिया और इसके बाद पीठासीन ने चर्चा की अनुमति दी। बहस लगभग दस घंटे तक जारी रही।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 20 बार रोका गया और बार-बार रूलिंग बुक दिखाई गई। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के सांसदों द्वारा बैन की गई किताबें सदन में पेश करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पक्षपात स्पष्ट होता है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब में कहा कि नेता प्रतिपक्ष अक्सर विदेश चले जाते हैं। (शेष पेज 10 पर)

संकट — होटल-रेस्टोरेंट बंद होने का खतरा, जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू...

कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई ठप

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली : अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग के कारण फारस की खाड़ी स्थित होर्मुज जलमार्ग पर गैस सप्लाई ठप हो गई है। इससे देश में एलपीजी की किल्लत पैदा हो गई है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लग गई है। गैस न मिलने से कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आई है। तेल कंपनियां रेस्टोरेंट एसोसिएशनों से संपर्क कर सप्लाई की दिक्कतों को समझने की कोशिश कर रही हैं।

केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए देशभर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। गैस की सप्लाई अब चार श्रेणियों में बाँटी गई है। पहली श्रेणी में घरेलू रसोई गैस और वाहनों में उपयोग होने वाली सीएनजी आती है, जिसे पहले की तरह पूरी सप्लाई मिलेगी। दूसरी श्रेणी में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को 70 प्रतिशत गैस मिलेगी। तीसरी श्रेणी में बड़े उद्योग और नेशनल ग्रिड से जुड़े कारखानों को 80 प्रतिशत गैस मिलेगी। चौथी श्रेणी में छोटे बिजनेस, होटल और रेस्टोरेंट को पुरानी खपत के हिसाब से 80 प्रतिशत गैस दी जाएगी।

राज्यों में हालात और सप्लाई प्रभावित क्षेत्र

उत्तर प्रदेश में बुकिंग के 4-5 दिन बाद भी गैस डिलीवर नहीं हो रही है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। गोरखपुर में घरेलू सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों के बाहर एक किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नागपुर में कॉमर्शियल गैस कटौती के कारण लगभग 20 प्रतिशत होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। अगर सप्लाई नहीं सुधरी तो अगले दो दिनों में आधे से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक में होटल उद्योग 'जरूरी सेवाओं' में आता है, लेकिन गैस न मिलने से बुजुर्ग, छात्र और मरीज प्रभावित हो रहे हैं।

संकट का कारण और सरकार के कदम

सप्लाई संकट का मुख्य कारण होर्मुज जलमार्ग का लगभग बंद होना है। यह मार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। अमेरिका-इजराइल के हमलों के बाद ईरान के ड्रोन हमलों से कतर का एलएनजी उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 40प्रतिशत एलएनजी कतर से आयात करता है। सरकार ने संकट से निपटने के लिए पांच कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। (शेष पेज 10 पर)